पावरलूम सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की मांग

हमारे प्रतिनिधि

मुंबई । कोरोना महामारी के असरग्रस्त टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज घोषित करना चाहिए ऐसी मांग मुंबई पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पेडिक्सिल) के चेयरमैन एम.ए.रामासामी ने की है।

पिडिक्सिल के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को एक आवेदन में तत्काल प्रभाव से एक साल का राहत पैकेज जारी करने की मांग की है.पावरलूम क्षेत्र के उद्यमियों को कार्यशील पूंजी पर ब्याज माफ करने को कहा गया है।इसने मई से जुलाई 2021 तक तीन महीने के लिए कपड़ा और मेडेफ्स पर जीएसटी छूट की भी मांग की है।

साथ ही एटीएफ के तहत बकाया सब्सिडी और सरकारी सहायता तत्काल जारी करने, सूत, कलपुर्जों, एक्सेसरीज आदि जैसे सभी कच्चे माल पर डंपिंग रोधी शुल्क और बुनियादी सीमा शुल्क में छूट देने और कपड़ा और मेडेफ्स निर्यात के सामने ड्यूटी ड्रा बैक दर बढाकर 8 से 10 प्रतिशत करने की मांग की गई है.

कपड़ा उद्योग के क्लअ क्षेत्र को भी अप्रैल 2021 से एक साल की मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान करने और अधिस्थगन अवधि के दौरान छह महीने की आस्थगित किश्तों पर ब्याज माफ करने के लिए कहा गया है। पेडिक्सिल के अध्यक्ष, एम.ए.रामासामी ने कहा कि कपड़ा उद्योग कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।कपड़ा उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पावरलूम है।यह 63 लाख श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है।भारत से होने वाले कपड़ा निर्यात में पावरलूम की हिस्सेदारी 60 फीसदी से ज्यादा है।यह एक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र है जो क्लअ इकाइयों से बना है।दुनिया के कई हिस्सों में घट रही कोरोना महामारी से भारत के आयात-निर्यात व्यापार में भी गिरावट आई है।कपड़ा बाजार, मॉल और खुदरा दुकानों के बंद होने से कपड़ा की मांग में गिरावट आई है और स्थानीय पावरलूम उद्योग की स्थिति खराब हो गई है।कोरोना के चलते लॉकडाउन,कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों के कारण, विशेष रूप से पावरलूम क्षेत्र में छोटी और मध्यम कपड़ा इकाइयों की हालत खराब हो गई है।उनके आदेश रद्द हो गए हैं, वसूली बंद हो गई है, श्रमिकों को वेतन देने के लिए मजबूर किया गया है और कार्यशील पूंजी की कमी है।ऐसे में सरकार को तत्काल आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि पावरलूम इकाइयों को और नुकसान न हो।

Scanned with CamScanner